प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2026**

विषय:- जनपद ललितपुर में जाखलौन पम्प नहर पर 3.42 मेगावाट क्षमता की कैनाल टॉप सोलर पी0वी0 प्लान्ट के निर्माण की पुनरीक्षित परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1264/387/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 18.06.2026 एवं शासनादेश संख्या-155/2021 /1528/21-27-सिं-9-71एसएवी/15, दिनांक 29.09.20221 एवं शासनादेश संख्या-233/2022/2048/22-27-सिं-9-71एसएवी/15, दिनांक 22.11.2022 एवं शासनादेश संख्या-157/2024/001/339(1)/24-27-सिं-9-71 एसएवी/15, दिनांक 28.03.2024 एवं शासनादेश संख्या-194/2024/001/780/24-27-सिं-9-71 एसएवी/15, दिनांक 22.05.2024 एवं शासनादेश संख्या-28/2026/001/22/26-27-सिं-9-71 एसएवी/15, दिनांक 23.01.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **जनपद ललितपुर में जाखलौन पम्प नहर पर 3.42 मेगावाट क्षमता की कैनाल टॉप सोलर पी0वी0 प्लान्ट के निर्माण की पुनरीक्षित परियोजना** की अनुमोदित लागत रू0 2964.31 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनु0 सं0-94 सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य) पूंजीलेखा पक्ष लेखाशीर्षक-4700-14-051-11-14-24 के अन्तर्गत प्राविधानित सम्पूर्ण धनराशि रू0 18,50,000.00 (रूपये अट्ठारह लाख पचास हजार मात्र) परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से वहन किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /विभाग का होगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

(6) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएल/डिपाजिट खाते में न रखें जायें।

(7) विभाग द्वारानियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स की सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।

(8) प्रायोजना का निर्माण कार्य पुनरीक्षित लागत में पूर्ण किया जाय। प्रायोजना का भविष्य में कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(9) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में कराये गये कार्यों की लागत को यथावत सम्मिलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(11) विभाग द्वारा अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-1606/दस-2014-17(4)/ 75,दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(12) 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(13) विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि में से सेन्टेज चार्जेज तथा लेबर सेस जमा किये जाने का साक्ष्य शासन को उपलब्ध कराया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये **18,50,000.00 (रूपये अट्ठारह लाख पचास हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 0**94 **लेखाशीर्षक** 4700140511114 सम्बद्ध कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजीव कुमार वत्स

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

(3) प्रमुख अभियन्ता (परियोजना),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।

(4) मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।

(6) अनु सचिव एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(8) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग-8 /वित्त(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।

(10) नियोजन अनुभाग-1

(11) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद यादव

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in